

## भाग ४ (ग)

### अन्तिम नियम

#### ऊर्जा विभाग

भोपाल, दिनांक 19 फारवरी 2001

क्र. 1086-एफ. 3-20-13-98.—इलेक्ट्रिसिटी रेयुलेटरी कमीशन एक्ट, 1998 (1998 का सं. 14) को धारा 19 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाने हुए राज्य सरकार, उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के बेतन, भर्ते तथा सेवा की लार्ज संरचित नियमित नियम बनाते हैं, अवश्यतः—

#### भाग-एक

(1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के बेतन, भर्ते और अन्य सेवा शर्तों) नियम, २००० है।

(2) वे नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रारूप होंगे।

2. परिभाषायें—इस नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अधिकृत न हो—

(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है इलेक्ट्रिसिटी रेयुलेटरी कमीशन एक्ट, 1998 (1998 का सं. 14);

(ख) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन स्थानित किए गए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष;

(ग) “सरकार” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश की सरकार;

(घ) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(ङ) “राज्यसभा” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल दिए गए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का सदस्य;

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त है, किन्तु जिन्हें परिभ्राष्ट नहीं किया गया है, वहों अर्थ होंगा, जो इलेक्ट्रिसिटी रेयुलेटरी कमीशन एक्ट, 1998 (1998 का सं. 14) में उनके लिए दिया गया है।

3. अध्यक्ष एवं सदस्यों के बेतन तथा भर्ते—(1) अध्यक्ष रूपये 26,000 (नियम) बेतन प्रतिमाह प्राप्त करेगा और सदस्य, बेतनमान रूपये 24050—650—26,000 प्रतिमाह में सेवा प्राप्त करेंगे।

परन्तु, किसी ऐसे ज्ञानिक के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति की दशा में जो किसी उच्च न्यायालय के रूप में सेवानिवृत्त हुआ है या जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है और जो पेशन अंतर्याम विधान या अन्य प्रकार की सेवानिवृत्त प्रसुविधाओं के तौर पर कोई सेवानिवृत्त प्रसुविधाएं प्राप्त करता है या जिसमें प्रसुविधाएं प्राप्त की हैं या जो प्राप्त करने का हकदार ही गया है, तो उसके बेतन में से सेवा उपदान, बदि कोई हो, के समतुल्य मेंशन की कुल रकम को घटा दिया जाएगा, किन्तु इसमें उसके द्वारा निकाले गये या निकाले जाने वाले सेवानिवृत्त उपदान के समतुल्य पेशन सम्मिलित नहीं है।

(2) अध्यक्ष या सदस्य, ऐसा भूमिकाएँ भरता प्राप्त करेंगे जो उनका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य में के नायाधीशीय भर्ते के अनुहोस त्रिष्णा (ग्रेड) के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अनुहोस है।

(3) अध्यक्ष, ऐसा नगर प्रतिकरणात्मक भर्ता तथा अन्य भर्ते प्राप्त करने का हकदार होगा, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुहोस है। सदस्य ऐसे नगर प्रतिकरणात्मक भर्ते के हकदार होंगे जो राज्य में के तत्त्वानीय त्रिष्णा (ग्रेड) के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अनुहोस है।

4. निवास—(1) अध्यक्ष, ऐसा किरायामुक्त तथा सुसंचित निवास, जल तथा विद्युत सुविधाओं का हकदार होगा, जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 एवं उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों के अधीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अनुहोस है। सदस्य निवास के आधार पर ऐसे निवास के लिए हकदार होंगे, जैसा कि प्रमुख सचिवों को अनुदेश किया जाए और उनके द्वारा किसान, ऐसे निवास के आधार पर देख होगा, जैसा कि राज्य के प्रमुख सचिवों द्वारा देय है।

(2) दूदि अध्यक्ष या सदस्य के लिए जास्तीय निवास स्थान को अप्रस्था नहीं की जाती है या वह राजसभाव निवास स्थान के उपर्योग की सुविधा का स्वर्वं उपभोग नहीं करता है तथा अपने स्वर्वं के मकान में निवास करता है तो उसे ऐसा मकान किराया भरता जा भुगतान किया जा सकेगा जैसा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या राज्य में के तत्त्वानीय त्रिष्णा (ग्रेड) के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अनुमति अनुहोस है।

5. आहन की सुविधा—(1) अध्यक्ष और सदस्यों के लिए पृथक् रूप से स्टॉफ कार और चालक (ड्राइवर) की व्यवस्था की जाएगी।

(2) अध्यक्ष, उनकी कार के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की लागू सेवा शर्तों के अनुसार 200 लीटर पेट्रोल का हकदार होगा। सदस्य उनकी कार के लिए स्थानीय कर्तव्य (इपूटी) के प्रबोधन के लिए 60 लीटर पेट्रोल में हकदार होंगे।

(3) अध्यक्ष तथा सदस्य प्राइवेट प्रयोजन के लिए उन नियमों के अनुसार शामकोय वाहन का उपयोग करने के हकदार होंगे, जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज में के तत्त्वानी श्रेणी (ग्रेड) के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को क्रमशः लागू हैं।

6. यात्रा भत्ता.—(1) अध्यक्ष, राज्य के भीतर या बाहर दौरे पर रहते समय या स्थानीतरण पर (विसके अंतर्गत आयोग (कमीशन) में पदग्रहण के लिए की गई यात्रा या आयोग (कमीशन) में उसकी कार्य अवधि के अवसान पर उसका गृह नगर को जाना आता है) यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, वैयक्तिक जीवज्ञान के परिवहन और उसके के राज्यन अन्य बातों का हकदार उन्हीं मान (स्केल) तथा उन्हीं दरों पर होगा, जैसा कि हाई कोर्ट जेल (ट्रेवलिंग अलाइन्स) रूल्स 1956 में विहित है।

(2) सदस्य, राज्य के भीतर या बाहर दौरे पर रहते समय या स्थानीतरण पर (विसके अंतर्गत आयोग में पदग्रहण के लिए की गई यात्रा या आयोग में उसकी कार्य अवधि के अवसान पर उसका गृह नगर को जाना आता है, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, वैयक्तिक जीवज्ञान के परिवहन और उसके के समान अन्य बातों के हकदार होंगे, जैसा कि राज्य में के तत्त्वानी श्रेणी (ग्रेड) के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अनुदेव है।

7. अवकाश यात्रा विवाहत.—अध्यक्ष और सदस्य, अवकाश यात्रा विवाहत के लिए वैशी ही दरों पर, वैसे ही मान (स्केल) और वैशी ही लातों पर हकदार होंगे, जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज में के तत्त्वानी श्रेणी (ग्रेड) के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को क्रमशः लागू हैं।

8. अवकाश.—(1) अध्यक्ष एवं सदस्य, सेवा के पूर्ण किए गए 6 मास के लिए 15 दिन की दर पर अवित्त अवकाश के हकदार होंगे, जैसे अक्षमिक अवकाश और आय अवकाश के भी हकदार होंगे, जैसा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और राज में के तत्त्वानी श्रेणी के अधिकारियों को क्रमशः अनुदेव है।

(2) अध्यक्ष या सदस्य, आयोग में उसकी पदाधिक की समाप्ति पर, उसके बातों में जमा आजित अवकाश के संबंध में अवकाश वेतन के समतुल्य नगद प्राप्त करने का हकदार होगा, परन्तु वह एवं जबकि भूताने नये अवकाश की मात्रा (कवान्टम) 90 दिन से अधिक न हो।

(3) अध्यक्ष और सदस्य, नियमित (2) के अधीन अवकाश वेतन पर भत्ता, उन्हीं दरों पर प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो कि आयोग में पदमुका होने की तारीख को प्रवृत्त दर पर अनुदेव है।

परन्तु वह ऐसे अवकाश वेतन पर नगर प्रतिकर्त्तव्यक भत्ता या अन्य किसी भत्ते का हकदार नहीं होगा।

9. अवकाश मंजूरी प्राधिकारी.—अध्यक्ष सदस्यों को अवकाश मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा, मध्यप्रदेश का राज्यपाल,

अध्यक्ष को अवकाश मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

10. चिकित्सीय उपचार सुविधा.—अध्यक्ष और सदस्य, वैसे ही चिकित्सीय उपचार सुविधा और अस्पताल मंजूरी सुविधाओं के हकदार होंगे, जैसा कि शासन के तत्त्वानी वेतन स्तर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य को अनुदेव है।

11. पेशन.—आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य, उनके द्वाएँ आयोग में की गई सेवा के लिए कोई पेशन तथा उपदान प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

12. भवित्व निधि.—अध्यक्ष या सदस्य, स्वयं के विकल्प पर भवित्व निधि में अधिदाय करने हेतु हकदार होंगे और उसके द्वारा विकल्प लेने की दशा में वह, मध्यप्रदेश सामान्य भवित्व निधि नियम, 1955 के उपचर्यों द्वारा शामिल होगा।

13. सदस्यों द्वारा शापथ—(1) आयोग का अध्यक्ष, अपने पद का पदभार ग्रहण करने से पूर्व इन नियमों से उपाबद्ध प्रूप में, आयोग के अध्यक्ष के समक्ष गद और गोपनीयता नी शापथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(2) आयोग का प्रत्येक सदस्य, अपने पद का पदभार ग्रहण करने से पूर्व, इन नियमों से उपाबद्ध प्रूप में, आयोग के अध्यक्ष के समक्ष गद और गोपनीयता नी शापथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(मध्यप्रदेश विद्युत् नियमक आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के लिए पद की शापथ का प्रूप)

(नियम 13 देखिए)

मेरे ..... मध्यप्रदेश विद्युत् नियमक आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाने पर इश्वर के नाम पर सत्यगीता से शपथ लेता हूँ और सत्यगीता से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन अद्विवेक और शुद्ध और ज्ञान से असंग और अपो वद के कर्तव्यों का निर्वहन भय या पश्चात, अनुराग या दुर्भिक्षण के बिना विधि के अनुसार करूँगा।

अध्यक्ष/सदस्य  
मध्यप्रदेश विद्युत् नियमक आयोग, भोपाल।

भोपाल : .....  
दिनांक : ..... 2000

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दं श. श. ए. ए. और, संघिय,

Bhopal, the 19th February 2001

F- No.1086-3-20-13-98.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 read with sub-section (2) of Section 19 of the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 (No. 14 of 1998), the State Government hereby make the following rules relating the pay, allowances and conditions of service of the Chairman and Members of the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, namely:—

#### PART—I

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Salary, Allowance and other service conditions of the Chairman and Members) Rules, 2000.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the " Madhya Pradesh Gazette".

**2. Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires:

- (a) "Act" means the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 (No. 14 of 1998);
- (b) "Chairman" means the Chairman of Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission Established under sub-section (1) of Section 17 of the Act;
- (c) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (d) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;
- (e) "Member" means the Member of Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission established under sub-section (1) of Section 17 of the Act;

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Electricity Regulatory Commissions Act, 1998 (No. 14 of 1998).

**3. Pay and Allowance of Chairman and Members.**—(1) The Chairman shall receive pay of Rs. 26,000/- (fixed) per mensem and the members shall

receive a pay in the scale of Rs. 24,030-000-20,000/- per mensem:

Provided that in the case of an appointment as Chairman or a Member, of a person who has retired as a Judge of a High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension and/or gratuity or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension equivalent of service gratuity if any but excluding pension equivalent of retirement gratuity, drawn or to be drawn by him.

(2) The Chairman or Members shall receive such Dearness Allowance as is admissible respectively to a High Court Judge and Officers of the Indian Administration Service of the corresponding grade in the State.

(3) The Chairman shall be entitled to receive city compensatory allowance and other allowances as are admissible to High Court Judge. The Members shall be entitled to City Compensatory Allowance as is admissible to the Officers of Indian Administration Service of the corresponding grade in the State.

**4. Accommodations.**—The Chairman shall be entitled to rent-free and furnish accommodation, water and electricity facilities as permissible to the High Court Judges under the provisions of High Court Judges (conditions of service) Act, 1954 and rules made thereunder. The Members shall be entitled to accommodation as may be admissible to Principal Secretaries on rental basis and rent will be payable by them on the basis of rent payable by Principal Secretaries of the State.

(2) The Chairman or a Member is not provided with or does not avail himself of the use of official residence and resides in his own house, he may be paid house rent allowance as admissible respectively to a High Court Judge or to the Officers of the Indian Administrative Service of the corresponding grade in the State.

**5. Facility of conveyance.**—(1) The Chairman and the Members shall be separately provided with a staff car and a driver.

(2) The Chairman shall be entitled to 200 liters of petrol for his car as per service conditions applicable to High Court Judge. The Members shall be entitled to 60 liter of petrol for their cars for the purpose of local duty.

(3) The Chairman and Members shall be entitled to use Government vehicles for private purpose as per rules applicable respectively to the High Court Judge and officers of the Indian Administrative Services of the corresponding grade in the State.

6. Travelling Allowance.—(1) The Chairman while on tour inside or outside the State or on transfer (including the journey undertaken to join the Commission or on the expiry of his term with the Commission to proceed to his home town) shall be entitled to travelling allowance daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same scale and at the same rates as are prescribed in the High Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1956.

(2) The members while on tour inside or outside the State or on transfer (including the journey undertaken to join the Commission or on the expiry of his term with the Commission to proceed to his home town) shall be entitled to travelling allowance, daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters as is admissible to the Officers of Indian Administrative Service of the corresponding grade in the State.

7. Leave Travel Concession.—The Chairman and Members shall be entitled to the leave travel concession at the same rates at the same scales and on the same conditions as per applicable to a High Court Judge and to the officers of the Indian Administrative Service of the corresponding grade posted in the State respectively.

8. Leave.—(1) The Chairman and the Members shall be entitled to earned leave at the rate of 15 days for every completed 6 months of service. They shall also be entitled to casual leave and other leaves as admissible respectively to the High Court Judge or to the officers of the Indian Administrative Service of the corresponding grade in the State.

(2) On the expiry of his term of office in the Commission, a Chairman or a Member shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary in respect of the earned leave standing to his credit provided that the quantum of leaves encashed shall not exceed 90 days.

(3) The Chairman and the Members shall be entitled to receive the dearness allowance on the leaves salary under sub rule (2) as admissible at the rates in force on the date of the relinquishment of the office in the Commission:

Provided that he shall not be entitled for the city compensatory allowance of any other allowance on such leave salary.

9. Leave sanctioning authority.—The Chairman shall be the authority competent to sanction leave to the members. The Governor of Madhya Pradesh shall be the authority competent to sanction leave to the Chairman.

10. Facilities for Medical Treatment.—The Chairman and the members shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as are admissible to a member of the Indian Administrative Service of the corresponding pay levels in the Government.

11. Pension.—The Chairman and the Members of the Commission shall not be entitled to receive any pension and gratuity for the service rendered by them in the Commission.

12. Provident Fund.—The Chairman or a Member shall be entitled to subscribe to provident fund at his option, and in case of his so opting shall be governed by the provisions of the Madhya Pradesh General Provident Fund Rules, 1955.

13. Oath by the Members.—(1) The Chairman of the Commission shall before entering upon his office, make and subscribe to an oath of office and secrecy before the Governor in the form annexed to these rules.

(2) Every member of the Commission shall before entering upon his office, make and subscribe to an oath of office and secrecy before the Chairperson of the Commission in the form annexed to these rules.

(Form of an Oath of Office for Chairman/Member of the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission)

(See Rule 13)

I....., having been appointed as Chairman/Member of the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, do solemnly swear in the name of God solemnly affirm that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Chairman/Member and perform the duties of my Office in accordance with law without fear or favour, affection of ill-will.

Chairman/ Member  
Madhya Pradesh Electricity Regulatory  
Commission, Bhopal.  
Bhopal  
Dated the....., 2000.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
D.R.S. CHAUDHARY, Secy.